web: www.nyaysakshi.com || पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल || पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक-सेहत-विज्ञान-फीचर

SJU Social Justice Union

दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, मंगलवार 27 अगस्त 2019 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-01, अंक- 327

नक्सल समस्या : केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की मंत्रणा

» नक्सलियों के खात्मे के लिए बनेगी नई रणनीति

रायपुर (आरएनएस)। नक्सल समस्या को लेकर आज नई दिल्ली में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली है। बैठक में प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल के साथ पुलिस विभाग के आला अफसर भी शामिल हुए। बैठक के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है।

देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके नक्सलियों के खिलाफ ठोस रणनीति बनाने आज केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक लेकर वर्तमान परिस्थितियों की समीक्षा की है। इस बैठक में देश के लिए नासूर बनते जा रहे माओवाद के खात्मे के लिए ठोस रणनीति बनाने अब मंथन चल रहा है। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज सोमवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित नक्सल प्रभावित 11 राज्यों के सीएम, डीजीपी और वरिष्ठ अफसर शामिल हुए। बैठक में नक्सल समस्या को जड़ से खत्म करने को लेकर चर्चा की गई। इसी बीच छत्तीसगढ़ में नक्सल हमले को लेकर हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ज्ञात हो कि देश में नक्सल समस्या से सबसे ज्याद प्रभावित छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के सभी जिलों के अलावा राजनांदगांव, कवर्धा,गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी जिले में नक्सलियों की सक्रियता अधिक है।

पूर्व पीएम मनमोहन की सुरक्षा में कटौती

» एसपीजी नहीं अब सिर्फ जेड+ सेक्योरिटी

नईदिल्ली,26 अगस्त (आरएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एसपीजी सुरक्षा हटा दी गई है और अब उन्हें सिर्फ जेड+ सुरक्षा ही दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि सुरक्षा को लेकर फैसला पूरी तरह से प्रफेशनल आधार पर किया गया है। मोदी सरकार की ओर से यह फैसला विभिन्न खुफिया एजेंसियों रॉ और आई की ओर से मिले इनपुट, कैबिनेट सचिव और गृह मंत्रालय के बीच तीन महीने की समीक्षा बैठक के बाद लिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में एक पत्र जारी कर पूर्व प्रधानमंत्री को जानकारी दे दी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, बीएसपी सांसद सतीश चंद्र मिश्रा, यूपी बीजेपी के नेता संगीत सोम, बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी की सुरक्षा घटा दी गई। इसके अलावा केंद्र ने यूपी सरकार के मंत्री सुरेश राणा, एलजेपी सांसद चिराग पासवान, पूर्व सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा में भी कटौती की। लालू प्रसाद के अलावा बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी की भी सुरक्षा में कमी की गई, उन्हें अब केंद्र की सुरक्षा नहीं मिलेगी। इसके अलावा राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा की सुरक्षा भी कम की गई।

महत्वपूर्ण एवं खास

सीबीआईसी ने की 22 अफसरों की जबरन छुट्टी

» करप्शन पर सरकार का वार

नईदिल्ली (आरएनएस)। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सरकारी विभागों की सफाई यानी नाकारा अफसरों को निकालने का सिलसिला लगातार जारी है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सोमवार को एक बार फिर 22 सीनियर अफसरों को जबरन रिटायर करने का फैसला लिया है. ये सभी अफसर टैक्स डिपार्टमेंट के हैं. इससे पहले भी टैक्स विभाग के ही 12 वरिष्ठ अफसरों को जबरन रिटायर कर दिया गया था. आपको बता दें कि इसके पहले जून महीने में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालते ही सख्त फैसला लेते हुए कई बड़े अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया था. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के नियम 56 के तहत वित्त मंत्रालय के इन अफसरों को सरकार समय से पहले ही रिटायरमेंट दे रही है. जून महीने में नियम 56 के तहत रिटायर किए गए सभी अधिकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर्स और कमिश्नर जैसे पदों पर तैनात थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से कई अफसरों पर कथित तौर पर भ्रष्टाचार, अवैध और बेहिसाब संपत्ति जैसे गंभीर आरोप थे.

गंगई अम्मन मंदिर के पास ब्लास्ट में शख्स की मौत

» पुलिस ने कहा अलर्ट से कनेक्शन नहीं

कांचीपुरम (आरएनएस)। तमिलनाडु के कांचीपुरम में गंगई अम्मन मंदिर के पास रविवार को धमाका हुआ. इस धमाके में एक व्यक्ति के मारे जाने की सूचना है, जबकि 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं. बम निरोधक दस्ते ने घटनास्थल पहुंच कर परिसर को अपने कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी है. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मंदिर के पास एक टैंक से कीचड़ निकाला जा रहा था. इस समय मजदूरों को एक अज्ञात बॉक्स मिला. जब मजदूरों ने उसे खोलने की कोशिश तो वह फट गया. इस धमाके में के. सूर्या नाम के शख्स की मौत हो गई और अन्य 5 लोग घायल हो गए. घायलों का नज़दीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है. वहीं, एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक, मंदिर के पास पांच संदिग्ध लोग घूम रहे थे. इनमें से एक के पास बॉक्स था. जब उन्होंने इस बॉक्स को खोलने की कोशिश की, तो बॉक्स में धमाका हो गया. पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि फिलहाल इस धमाके हाई अलर्ट से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में आतंक को लेकर जारी अलर्ट से इसका कोई संबंध नहीं है. आतंकियों के प्रदेश में प्रवेश करने की जानकारी के बाद अलर्ट जारी किया गया है.

शिमला में बादल फटा, मणिमहेश यात्रा भी रोकी गई

शिमला (आरएनएस)। हिमाचल की राजधानी शिमला के रामपुर में बादल फटा है. यहां मूसलाधार बारिश की वजह से किन्नौर, रिकॉन्गपिओ, छितकुल, और लाहौल स्पीति को जोड़ने वाला हाईवे बंद हो गया है. वहीं, चंबा में मणिमहेश यात्रा भी रोकी गई है. क्योंकि मणिमहेश जाने वाले रास्ते पर एक पुलिया बह गई है. चंबा पुलिस के अनुसार, चंबा के भरमौर हड़सर मार्ग पर प्रचाला में पुलिया बही है. इसी वजह से यात्रा रोकी गई है. फिलहाल, राहत और बचाव कार्य जारी है. जानकारी के अनुसार, रविवार रात को भारी बारिश के चलते शिमला से 100 किमी दूर रामपुर बुशहर में जेओरी के समीप बधाल में बादल फटा है. बधाल बाज़ार में दुकानों पर मलबा गिरा है. एनएच-05 पर मलबे के साथ पेड़ गिरे हैं और इससे कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है. एनएच 05 पर किन्नौर और काजा (स्पीति) जाने वाले वाहनों के पहिये थम गए हैं. हिमाचल प्रदेश में 31 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. सोमवार को प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी. मध्यपर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में बारिश का अनुमान है. इसके अलावा,उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में एक दो जगहों पर बारिश के आसार हैं.

आतंकी हाफिज सईद के साथ लाहौर में लगे पोस्टर

» फिर बेनकाब हुए इमरान खान

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पूरी दुनिया में कितना भी घूम-घूमकर खुद को और अपनी सरकार को पाक-साफ बताएं और भारत के खिलाफ आग उगलें लेकिन आए दिन वे लगातार बेनकाब हो रहे हैं। इसी क्रम में मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साथ पाकिस्तान में उनके पोस्टर लगे हुए हैं। पोस्टर की फोटो पाकिस्तानी पत्रकारों ने ही सोशल मीडिया पर शेयर कर इमरान पर सवाल उठाए। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल, इस पोस्टर में साफ-साफ दिख रहा है कि आतंकी हाफिज सईद के बिलकुल बगल में ही इमरान खान की फोटो लगी हुई है, साथ ही अन्य कइयों की तस्वीर भी लगी हुई है। पोस्टर में उर्दू में सबके नाम लिखे हुए हैं। साथ ही उर्दू में ही जश्न-ए-आजादी भी लिखा हुआ है। इस पोस्टर के साथ ही इमरान खान के उस दावे की पोल खुल गई है जिसमें वे पूरी दुनिया में कहते घूमते हैं कि हम आतंकवाद से निजात पाना चाहते हैं।

राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने चक्रवात पर परमाणु बम गिराने की सलाह दी

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने देश में आनेवाले चक्रवातों पर, यहां पहुंचने से पहले ही परमाणु बम गिराने की सलाह दी है। राष्ट्रपति का कहना है कि इससे चक्रवात का आवेग बाधित हो जाएगा। एक्सियोस नाम की एक समाचार वेबसाइट में प्रकाशित खबर के अनुसार चक्रवात को लेकर हुई एक बैठक में ट्रंप ने जानना चाहा कि क्या अफ्रीका के तट पर चक्रवात बनने की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए, तूफान पर ही परमाणु बम गिराया जा सकता है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि ऐसा किया जा सकता है, जिससे वहां मौजूद कुछ अधिकारी हैरान रह गए।

वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में शामिल हुए सदस्य ट्रंप के सुझाव से हैरान-परेशान हो गए। उनमें से कुछ अधिकारी लगभग खीजते हुए कहने लगे, 'यह क्या है... हम इसका क्या करें ? इस पर क्या कहा जा सकता है।' वेबसाइट में यह नहीं बताया गया है कि यह बातचीत कब हुई। बताया जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस तरह की टिप्पणी पहली बार नहीं की है। 2017 में ट्रंप ने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी से पूछा था कि क्या चक्रवातों के आने से पहले ही उन पर परमाणु बम गिराया जा सकता है।

एक्सियोस वेबसाइट में प्रकाशित खबर के अनुसार, जिस वक्त अधिकारी राष्ट्रपति को अफ्रीकी तट पर आए चक्रवात के हालात के बारे में जानकारी दे रहे थे, उन्होंने अचानक ही यह सुझाव दिया। अधिकारी को बीच में ही रोकते हुए ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे चक्रवात के प्रभाव को कम करने का आइडिया मिल गया है। हम क्यों न चक्रवात के अटलांटिक तक पहुंचने से पहले ही उस पर परमाणु बम गिरा दें। इसके जवाब में अधिकारी ने कहा कि सर हमने आपके सुझाव को शामिल कर लिया है। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अधिकारी ने इसके बाद भी कई बार इस सुझाव को दोहराया जिससे मौजूद अधिकारी हैरान रह गए।

खबर के मुताबिक वाइट हाउस ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रेजिडेंट ट्रंप का उद्देश्य बुरा नहीं है। वह सिर्फ तूफान से होनेवाले संभावित खतरों को कम से कम करना चाहते हैं। वेबसाइट के अनुसार, ट्रंप का यह विचार नया नहीं है। इससे पहले 1950 में राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहोवर के कार्यकाल में एक सरकारी वैज्ञानिक ने यह सलाह दी थी। बार-बार उठने वाले इस विचार पर वैज्ञानिक पहले भी असहमति जता चुके हैं। अमेरिका में अक्सर चक्रवात आते रहते हैं।

अमेजन आग: जी-7 में विश्व नेताओं ने ब्राजील की मदद का किया ऐलान

रियो डि जनेरिया। जी-7 समूह के नेताओं ने अमेजन रेनफॉरेस्ट में लगी आग से निपटने में ब्राजील की मदद करने का रविवार को संकल्प जाहिर किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बताया कि शिखर सम्मेलन के नेता ब्राजील की सहायता करने के लिए, एक समझौते के करीब हैं। उन्होंने बताया कि इस समझौते में तकनीकी और वित्तीय तंत्र दोनों शामिल होंगी। जर्मनी की चांसलर आंगेला मर्केल ने भी ब्राजील की मदद का ऐलान किया है।

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि हम विभिन्न उपायों पर विचार कर रहे हैं ताकि हम सबसे प्रभावी तरीके से उनकी मदद कर सकें।' जर्मनी की चांसलर आंगेला मर्केल ने कहा कि आग पर काबू पाए जाने के बाद उनका देश और अन्य देश अमेजन में फिर से वन लगाए जाने पर ब्राजील से बात करेंगे। उन्होंने कहा 'बिल्कुल (यह) ब्राजील का क्षेत्र है, लेकिन हमारे सामने वर्षा वनों पर एक सवाल खड़ा है जो वास्तव में एक वैश्विक प्रश्न है।पृथ्वी के फेफड़े (महत्वपूर्ण वर्षा वन क्षेत्र) प्रभावित हुए हैं, इसलिए, हमें एक साझा समाधान खोजना होगा।'

पोप फ्रांसिस ने भी ब्राजील में लगी आग को लेकर चिंता जाहिर की और लोगों से प्रार्थना करने की अपील की ताकि उस पर जल्दी से जल्दी काबू पा लिया जाए। सेंट पीटर स्क्वॅयर में उन्होंने लोगों से कहा कि अमेजन में लगी आग को लेकर हम चिंतित हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेजन वर्षा वन क्षेत्र हमारी पृथ्वी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। उन्होंने बताया कि इज़राइल आग से निपटने के लिए एक विशेष विमान भेजेगा। शुक्रवार को उन्होंने ऐलान किया था कि उनकी सरकार अमेजन क्षेत्र के वर्षा वनों में लगी आग पर काबू पाने में मदद के लिए 44,000 सैनिक भेजेगी। लेकिन अब तक कुछ सौ सैनिक ही भेजे गए हैं।

एनबीसीसी को मिलेंगे 7.16 करोड़

» आम्रपाली मामले में सुको का फैसला

नईदिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम्रपाली ग्रुप के मामले में अहम आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों की याचिका पर आम्रपाली के अटके प्रोजेक्ट्स पूरा करने के लिए नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) को 7.16 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया है. इतना ही नहीं आम्रपाली के डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स से मकान खरीददारों के 3 हजार करोड़ कैसे वसूले जाएंगे इसकी भी प्लानिंग की गई है.

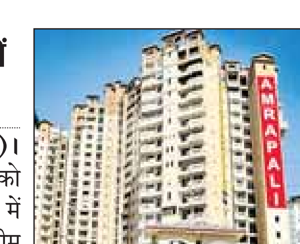

बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को आदेश दिया कि वह एनबीसीसी को फंड दे ताकि अधर में लटके हुए फ्लैट्स का काम हो सके. फिलहाल बेंच ने 7.16 करोड़ रुपये देने को कहा है. यह पैसा आम्रपाली ग्रुप ने ही सुप्रीम कोर्ट के पास जमा किया था. जिन दो प्रोजेक्ट्स के लिए यह पैसा दिया जाएगा वह नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हैं.

सोमवार को मामले की सुनवाई हुई. इसमें जस्टिस अरुण मिश्रा और यू यू ललित की बेंच ने सुनवाई की. उन्होंने फॉरेंसिक ऑडिटर्स को आदेश दिया है कि रिपोर्ट को प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली पुलिस और इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया को भेजा जाए.

पंचायत के आदेश पर महिला के बाल काटे, निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया

रांची (आरएनएस)। झारखंड के कोडरमा स्थित मरकच्चो प्रखंड के देंगोडीह गांव में भतीजे से शारीरिक शोषण का आरोप झेल रही पीड़िता का महिलाओं की कथित पंचायत में निर्वस्त्र कर बाल काटे जाने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि महिला का शारीरिक शोषण उसका भतीजा ही कर रहा था. फिर बाद में महिला को ही दोषी करार दिया गया. यह फैसला और कहीं नहीं, बल्कि मंदिर के पास लगाई गई महिलाओं की कथित पंचायत में ही किया गया.

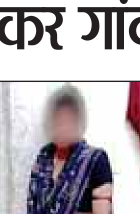

जानकारी के अनुसार, महिलाओं की कथित पंचायत में पहले तो महिला को घर से पंचायत तक घसीट कर लाया गया और उसके बाद निर्वस्त्र कर उसके बाल काट दिए गए. इतना ही नहीं फिर उसे ऐसी अवस्था में सरेआम गांव में घुमाया गया. पीड़ित महिला ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है.

पीड़ित महिला की मानें तो पिछले 3 महीने से पति की गैरमौजूदगी में उसका भतीजा लगातार उसका शारीरिक शोषण कर रहा था. जब यह बात महिला ने लोगों को बताई तो उस पर ही सारा आरोप लगाकर पंचायत में उसे निर्वस्त्र कर उसके बाल काटकर उसे सजा दी गई. पंचायत के इस तुगलकी फरमान और सजा के बाद पीड़ित महिला और उसका पूरा परिवार सकते में है. जिस दिन महिलाओं की पंचायत में पीड़िता को सजा सुनाई गई उसके एक दिन पहले ही उसका पति घर वापस आया था. उसे इस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं था. हालांकि जब उसकी पत्नी को महिलाओं की कथित पंचायत में घर से ले जाया जा रहा था तब उसने पत्नी को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन तब उसकी किसी ने नहीं सुनी.

चिदंबरम को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई याचिका

» आईएनएक्स मीडिया केस

नईदिल्ली (आरएनएस)। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया केस में केंद्रीय जांच एजेंसी के शिकंजे में हैं. दिल्ली हाईकोर्ट के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी करारा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा चिदंबरम की अंतरिम जमानत रद्द होने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस भानुमती की बेंच ने कहा कि जब सीबीआई ने उन्हें कस्टडी में लिया है, तो ऐसे में हम अंतरिम जमानत रद्द होने के फैसले को खारिज नहीं कर सकते.

चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका मामले में जस्टिस भानुमती ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद अग्रिम जमानत की अर्जी निष्प्रभावी हो जाती है. इस पर चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा फिर भी सुनवाई हो सकती है. जीवन का अधिकार महत्वपूर्ण है. इसपर जस्टिस भानुमति ने कहा कि अग्रिम जमानत को हम रेग्युलर बेल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, रिमांड के खिलाफ अर्जी लिस्ट नहीं है, हम लिस्टिंग के लिए नहीं कह सकते है.

इस बीच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) चिदंबरम की कस्टडी बढ़ाने की तैयारी कर रही है. चिदंबरम के सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ईडी उन्हें हिरासत में लेकर और पूछताछ करना चाहेगी. इसके लिए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है. ईडी का कहना है कि पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने अपने करीबियों और आईएनएक्स मीडिया केस के साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर भारत और विदेश में मुखौटा कंपनियों (शेल कंपनियों) का जाल बनाया.

बता दें कि सीबीआई ने चिदंबरम को 21 अगस्त की रात को जोरबाग स्थित उनके घर कस्टडी में लिया. उनकी कस्टडी सोमवार को खत्म हो रही है.

ईडी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, उनके पास अपने दावों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. ईडी का ये भी कहना है कि मुखौटा कंपनियों (शेल कंपनियों) का संचालन करने वाले लोग चिदंबरम के संपर्क में थे. ईडी चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ के दौरान ही इन सबूतों को उजागर करेगी.